नईदुनिया

संपादकीय

'स्विंग स्टेट' ने अमेरिका में पलटी बाजी

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बाजी अपने नाम कर ली है। उन्होंने बहुमत के जरूरी आंकड़े से कहीं अधिक मत हासिल कर लिए हैं। सर्वेक्षणों में नतीजे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पक्ष में जाते दिख रहे थे। मगर मतदान के आखिरी दिन कांटे की टक्कर नजर आने लगी। ट्रंप को उन सात राज्यों में भी बढ़त हासिल हुई, जो पलटी मारने वाले राज्य यानी 'स्विंग स्टेट' माने जाते हैं। हालांकि ये नतीजे हैरान करने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उसी वक्त कमजोर पड़ने लगी थी, जब ट्रंप के आक्रामक चुनाव प्रचार के सामने राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी अस्वस्थता के चलते शिथिल नजर आने लगे थे। उसके बाद कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया।

मगर पार्टी के भीतर ही उथल-पुथल शुरू हो गई थी। इस तरह कमला हैरिस को समय कम मिल पाया। हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी और महिला मतदाताओं को लुभाने में कामयाब भी रहीं। मगर ट्रंप ने कमजोर अर्थव्यवस्था, महंगाई और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बाइडेन सरकार पर निशाना साधा, और उसका असर वहां के मतदाताओं पर पड़ा। हालांकि इन मसलों पर ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत आक्रामक ढंग से काम किया था। उसी का प्रभाव था कि इस बार के चुनाव प्रचार में वहां के कई बड़े उद्योगपति भी उनके साथ मंच पर उतरे थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हालांकि अब भी बहुत खराब नहीं है, मगर पहले की तुलना में उसकी रफ्तार धीमी जरूर पड़ गई है। उस पर मंदी की मार है। महंगाई अब तक के पचास वर्षों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने वादा किया कि वे एक करोड़ अवैध प्रवासियों को देश से निकाल बाहर करेंगे, उन पर करोड़ों डालर खर्च हो रहा है, तो वहां के युवाओं में नए अवसर की उम्मीद जगी। पिछले कार्यकाल में भी उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन हासिल था।

इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप आक्रामक ढंग से प्रशासन चलाने में विश्वास करते हैं और आर्थिक नीति तथा विदेश नीति को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। वे रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उसे रुकवा देंगे। इस तरह उन पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जिस तरह कई बार राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ीं, उसकी भरपाई वे कभी नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे तो शायद वे पार पा लें, मगर विदेश नीति को लेकर उन्हें सदा संदेह की नजर से देखा जाता रहा है। चीन के प्रति उनका रुख बहुत सख्त है। इस वक्त दुनिया में जिस तरह के समीकरण हैं, उसमें वैश्विक दक्षिण की अहमियत बढ़ी है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कोई तनाव नहीं है, मगर चीन और रूस के साथ अमेरिकी रिश्ते तल्ख होंगे तो भारत के साथ भी समीकरण गड़बड़ होने का खतरा हो सकता है। सबसे अहम बात कि अगर ट्रंप आव्रजन नीति में बदलाव करते हैं, तो वहां रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर, दुनिया में बढ़ रहे जलवायु संकट को लेकर ट्रंप संजीदा नहीं रहे हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के काम करने के तरीके पर लगातार सवाल उठते रहे। अगर इस बार भी उनका वही रुख रहेगा, तो उनका विवादों से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

पिछले वाले से अलग होगा ट्रंप का दूसरा कार्यकाल

संजय बारू

दुनिया में और किसी भी सार्वजनिक पद के लिए होने वाला चुनाव वैश्विक स्तर पर इतना ध्यान आकर्षित नहीं करता जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना। अमेरिका दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश बना हुआ है। इसका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी तकनीकी श्रेष्ठता एवं वैज्ञानिक आधार और सबसे विशाल सशस्त्र सेनाओं की अध्यक्षता करता है। हालांकि, यह अभी भी किसी महिला को अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बार के चुनाव में अपने महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह युक्त व्यक्तित्व के बावजूद हिलेरी क्लिंटन और कमला हैरिस को हरा डाला। जाति और वर्ग के वर्चस्व वाली राजनीति में, लैंगिक पहलू पीछे छूट गया। जनमत सर्वेक्षण एक बार फिर से उलट सिद्ध हुए।

बर्लिन से लेकर टोक्यो, मॉस्को से बीजिंग, तेल अवीव से लेकर तेहरान और वास्तव में, नई दिल्ली तक भी, प्रत्येक सरकार ट्रम्प द्वारा अपनी टीम के चयन पर बारीक नज़र रखेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा, उन्होंने पिछले कई सहयोगियों से किनारा कर लिया तो वहीं कइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। दुनिया ट्रंप को नए सिरे से देखेगी क्योंकि राष्ट्रपति के इर्द-गिर्द नए चेहरे होंगे और व्हाइट हाउस में उनके पिछले कार्यकाल के बाद से दुनिया बदल चुकी है।

घरेलू स्तर पर, ट्रंप का पहला काम स्थिरता सुनिश्चित करना और अपने अल्प-सुविधा प्राप्त समर्थकों, खासकर कामकाजी वर्ग को, उम्मीद प्रदान करना होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में ठीक-ठाक आगे बढ़ रही है, आर्थिक विकास 2 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, बेरोजगारी ट्रंप के मुख्य मतदाताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एक तरफ अपने जैसे करोड़पति और अरबपति वर्ग का लालचीपन तो दूसरी तरफ कम आय वाले और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दबे अपने समर्थकों की ज़रूरतों के बीच वे संतुलन कैसे बना पाएंगे, यह देखना बाकी है।

विदेशी मामलों में, ट्रंप यूरोप और पश्चिम एशिया में संघर्ष को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार में आर्थिक और विदेश नीति पर 'वाशिंगटन सर्वसम्मति' नामक रुख त्यागने का वादा किया था। उनसे उम्मीद की जाती है वे रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ मित्रता बनाएंगे। परंतु चीन को लेकर कयास है कि सख्त रुख अपनाते हुए उसके उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क ठोकेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि व्यावहारिक समझौतावादी रुख अपनाएं। पश्चिम एशिया में, उनसे ईरान को निशाना बनाने की उम्मीद की जा रही है, शायद सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव डालते हुए, कदाचित वे इस्राइल के बेंजामिन नेतन्याहू पर नकेल कसना चाहेंगे।

इनमें से प्रत्येक अपेक्षित कार्रवाई का दीर्घकालिक असर अमेरिका और दुनिया पर होगा। क्योंकि ट्रम्प ने अगले चार वर्षों में 'अमेरिका को पुन: महान बनाने' का वादा किया है। ट्रिलियन-डॉलर का सवाल यह है कि क्या ट्रम्प संविधान में बदलाव करते हुए एक व्यक्ति को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाला प्रावधान बनवाने हेतु दबाव डालेंगे। जो भी हो, लेकिन ट्रम्प का द्वितीय कार्यकाल उनके प्रथम वाले से अलग रहने की उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि उम्र और समय उनके पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका का शासन कैसे चलाया जाए, बेशक ट्रम्प इस पर एक दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन दुनिया को अपने नजरिए और अपनी पसंद के अनुसार चलाने की अमेरिका की क्षमता तेजी से सीमित होती जा रही है। अमेरिका को सहयोगियों और दोस्तों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यूरोप और जापान दोनों ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने को लेकर चिंतित हैं। पिछली बार, यूरोप में एंजेला मर्केल और जापान में शिंजो आबे थे। हाल की घड़ी, यूरोपीय या पूर्वी एशियाई नेताओं में कोई एक ऐसा नहीं है जो ट्रम्प के सामने तनकर खड़ा हो सके या उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो, बल्कि शायद उनके पिछलग्गू बन जाएं। पुतिन को राहत मिलेगी या नहीं और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नर्म पड़ने के लिए कहा जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रम्प और उनके सलाहकार अमेरिका के 'डीप स्टेट' एवं सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ और रूस के प्रति बाइडेन के दृष्टिकोण के पीछे कारक रहे तत्वों पर कितना नियंत्रण बना पाएंगे। हालांकि, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों, कम से कम शुरुआत में, ट्रम्प प्रशासन के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। विडंबना और कयास के विपरीत, हो सकता है कि ट्रम्प का पहला साल बाइडेन के आखिरी वर्ष की निस्बत वैश्विक रूप से अधिक शांत रहे।

सौभाग्यवश, भारत के समीकरण राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों ने, ट्रम्प के नजदीकी दायरे के लोगों के साथ संपर्क कायम रखा। हालांकि, भारतीय नेतृत्व को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि ट्रम्प का द्वितीय कार्यकाल, तमाम संभावनाओं के साथ, पिछले वाले से अलग होने वाला है। भारत के लिए नीतिगत रुचि के क्षेत्र में, ट्रम्प की आयात-निर्यात नीति और 'अमेरिका फर्स्ट' वाला दृष्टिकोण जिन विषयों में चुनौती पेश कर सकता है, वह हैं, व्यापार, आव्रजन और जलवायु परिवर्तन। मैं उदार अमेरिकी वीज़ा व्यवस्था का बड़ा समर्थक नहीं रहा क्योंकि यह भारत से प्रतिभाओं के पलायन में मददगार रहा। अगर ट्रम्प के कुछ पुराने सलाहकारों, विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइज़र जैसे लोगों की राष्ट्रपति कार्यालय में वापसी हो गई तो परस्पर व्यापार में चुनौती बन सकती है। रक्षा उपकरण खरीद और आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत का अमेरिका के साथ जुड़ाव बना रहेगा। हालांकि, मोदी सरकार को सावधानी से कदम बढ़ाने और अमेरिका के राजनीतिक व्यूह में न फंसने की सलाह है, जो कि पिछले चार वर्षों में हम कर चुके हैं। शायद गुरपतवंत सिंह पन्नूवाला मामला खत्म नहीं होगा क्योंकि यह पहले ही अदालत में चल चुका है। इस केस से उठती लहरें भारतीय तटों को छूती रहेंगी। ट्रम्प के प्रथम कार्यकाल के दौरान, शिंजो आबे पहले राजनेता थे जिन्होंने व्हाइट हाउस का दरवाज़ा खटखटाया, दोस्ताना हाथ बढ़ाया, एक अहंकारी को तुष्ट किया और क्वाड जैसा संगठन बनाने का विचार सिरे चढ़ाया, जिसका लाभार्थी भारत रहा।

नदी जोड़ो अभियान में अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

तान्त्या

मध्यप्रदेश ने अनेक विधाओं में अपना अग्रणी स्थान बनाया है। इनमें स्वच्छता अभियान सबसे प्रमुख है। इसमें मध्यप्रदेश अपना अग्रणी स्थान बना चुका है। समृद्धि के लिये कृषि और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है। कृषि विकास एवं औद्योगीकरण दोनों केलिये आधारभूत आवश्यकता जल है। जल की उपलब्धता का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत प्रकृति और वर्षा है जो नदियों, पोखरों और तालाबों के माध्यम से सुलभ होता है। मध्यप्रदेश नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत केन-बेतवा परियोजना और नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के साथ जल संचय जन भागीदारी-जन आंदोलन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त दस हजार से अधिक तालाब, पोखर और कुओं का जीर्णोद्धार हुआ।

मनुष्य जीवन के निर्माण और विकास में नदियां सदैव केंद्र में रही हैं। संस्कृतियों का निर्माण नदी तट पर ही हुआ है। जीवन को पुष्पित-पल्लवित करने में नदी और नदी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। इसीलिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के अभियान में नदियों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में ही राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाके क्रियान्वयन के निर्देश दिये। यह परियोजना समूचे देश के लिये है। इसके अंतर्गत कुल 30 रिवर-लिंक बनना हैं इनके माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों की कुल 37 नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना है। परियोजना में कुल 15 हजार किलमीटर लंबी नई नहरों का निर्माण होना है। इससे रिवर लिंक एवं नहरों के विशाल नेटवर्क से कृषि और अन्य उपयोग के लिये पानी की उपलब्धता के साथ धरती का गिरता जल स्तर भी संतुलित होगा।

मध्यप्रदेश ने अनेक विधाओं में अपना अग्रणी स्थान बनाया है। इनमें स्वच्छता अभियान सबसे प्रमुख है। इसमें मध्यप्रदेश अपना अग्रणी स्थान बना चुका है। समृद्धि के लिये कृषि और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है। कृषि विकास एवं औद्योगीकरण दोनों केलिये आधारभूत आवश्यकता जल है। जल की उपलब्धता का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत प्रकृति और वर्षा है जो नदियों, पोखरों और तालाबों के माध्यम से सुलभ होता है। मध्यप्रदेश नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत केन-बेतवा परियोजना और नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के साथ जल संचय जन भागीदारी-जन आंदोलन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त दस हजार से अधिक तालाब, पोखर और कुओं का जीर्णोद्धार हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदभार संभालते ही एक ओर नदी जोड़ो परियोजनाओं का काम आरंभ किया और दूसरी ओर तालाब, कुआं, बावड़ी और पौखरों का जीर्णोद्धार अभियान चलाया। इससे गांवों में जल की उपलब्धता भी बढ़ी और धरती की उर्वरक क्षमता भी। यह जल की उपलब्धता का ही प्रभाव है कि इस वर्ष मध्यप्रदेश का कृषि उत्पादन 214 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 545 लाख मीट्रिक टन हो गया। अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश को भारत सरकार से प्रशंसा भी मिलीहै। कृषि उत्पादन वृद्धि में मिली प्रशंसा के बाद अब मध्यप्रदेश नदी जोड़ो एवं जल संचय अभियान में भी अग्रणी राज्य बना।

नदियों की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक समृद्ध प्रदेश है। नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा, शिप्रा, सोन जैसी सदानीरा नदियों का उद्गम मध्यप्रदेश है। ये नदियाँ अपनी विपुल जल राशि से प्रदेशवासियों को तो तृप्त करती ही हैं साथ ही अपने पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों की नदियों को जल से समृद्ध करतीं हैं। दो दशक पूर्व जल और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के अभाव में मध्यप्रदेश बीमारू राज्य रहा है। लेकिन अब मध्यप्रदेश ने विकास की नई अंगड़ाई ली है और विकास के विभिन्न कीर्तिमान बनाये हैं। विकास की इस धारा को अब डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने आगे बढ़ाया है, जल संरक्षण एवं जल संचय की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये हैं और अन्य प्राँतों की तुलना में अग्रणी स्थान पर पहुंच रहा है।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बना। इनमें बेतवा-केन लिंक परियोजना और चंबल-सिंध-पार्वती लिंक परियोजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये भारत सरकार ने 44605 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के अंतर्गत 221 किलोमीटर लंबी नहरों के माध्यम से केन और बेतवा के जल को जोड़ना है। ये दोनों नदियां मध्यप्रदेश से निकली हैं और यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। नदी जोड़ो योजना के लिये केन्द्र से सहमति मिलते ही मध्यप्रदेश सरकार ने तेजी से क्रियान्वयन आरंभ किया। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिस पर काम शुरू हो सका। इसके अंतर्गत केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी में भेजा जाना है। यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी होगी। परियोजना से लाभान्वित होने वाला अधिकांश क्षेत्र बुंदेलखंड है। सामान्यता बुन्देलखण्ड की गणना देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र में होती है। यहाँ नदियाँ होने के बावजूद पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी नदियों की जल क्षमता है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद न केवल बुन्देलखण्ड में जल की उपलब्धता होगी अपितु धरती के जल स्तर में भी सुधार होगा। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी। इसके अतिरिक्त 103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन भी आरंभ हो सकेगा।

दूसरी पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना है। यह लगभग बीस वर्षों से अटकी हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों से चर्चा कर बाधाओं को दूर किया। इस योजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश में मालवा और चंबल क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और शाजापुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा सहित कुल 12 जिले लाभान्वित होंगे। मध्यप्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना से जल की उपलब्धता जल संवर्धन के साथ विकास की नवीन ऊंचाईयों को छूने की उम्मीद की जा सकती है।

आजकल

उमर अब्दुल्ला कर रहे अपने चुनावी वादे का निर्वाह

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पास होना एक तरह से सत्तारूढ़ दल का अपने वादे का निर्वाह करना ही है। इस बार वहां के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली प्रमुख मुद्दा था। इसे नैशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने वादों में शामिल किया था। दरअसल, अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा स्वत: समाप्त हो गया था।

फिलहाल जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है। इसलिए वहां शासन संबंधी बहुत सारी शक्तियां उपराज्यपाल में निहित हैं। जबकि वहां की सरकार का वादा है कि वह लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा तभी संभव होगा जब उसका विशेष राज्य का दर्जा बहाल हो।

प्रस्ताव में भी कहा गया है कि विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने की मांग करती है। इनसे जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। हम इसे एकतरफा हटाए जाने से चिंतित हैं। विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करे और एक संवैधानिक रास्ता निकाले। प्रस्ताव में कहीं भी अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं कही गई है। यानी जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस मसले को तूल देने के बजाय विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। उधर, जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने पूर्ण राज्य के दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र को पहले ही भेज दिया था। केंद्र सरकार भी कहती आ रही है कि बहुत जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। मगर असल अड़चन इसी मसले पर आ सकती है कि उसके विशेष राज्य के दर्जे को किस रूप में सुरक्षित रखा जाए। जिस कश्मीरियत की बात की जाती रही है, उसे इसी के जरिए सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया जा सकता है। इस संवैधानिक पहलू पर केंद्र और राज्य सरकार किस तरह तालमेल बिठा पाती हैं, देखने की बात है।

आखिर आतंकवाद चाहता कौन है ?

योगेश कुमार सोनी

पड़ोसी देश से आतंकवाद पर कई बार चर्चा हुई लेकिन आजादी लेकर आज तक कोई हल नहीं निकला। हमें सबसे पहले उन लोगों पर एक्शन लेना होगा जो अपने ही देश में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह स्पष्ट है हर सरकार के कालखंड में वह खुलकर अंजाम देते आ रहे हैं। हर सरकार इसके इसके लिए चिंतित तो जरूर दिखती है लेकिन जनता के मन में प्रश्न जरूर आता है कि बिना किसी की मिलीभगत से आतंकवाद कैसे संभव है। वैसे तो पूरे देश की जनता के लिए मुद्दा सुरक्षा का होता है लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए यह सर्वप्रथम रहता है। नई सरकार गठित होते ही जिस तरह आतंकवादियों हमले करते जा रहे हैं उससे वह क्या संदेश देना चाहते हैं यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद लगातार हो रहे आतंकी हमलों से हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात से हैरान भी हैं कि आमजन में दहशत क्यों फैलाई जा रही है। आश्चर्य इस बात का भी है कि इस बार एक माह के भीतर हमले वहां हुए जहां पहले कभी नहीं हुए। मजदूरों तक को निशाना बनाया गया।

इस विषय में सभी दलों के बड़े नेताओं से चर्चा भी हुई तो उन्होंने आतंकवाद का एक सुर में विरोध किया। यह सुनकर अच्छा भी लगा कि हर कोई आतंकवाद के विरुद्ध है। यहां समझना जरूरी है कि विशेषज्ञों का बड़ा तबका यह मानता है कि किसी भी प्रकार का हमला बिना किसी नेता या बड़े रसूख वाले व्यक्ति की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। हालांकि पूर्व में जो भी हमले हुए, उनके बारे में पुलिस जांच का निष्कर्ष है कि इनमें स्थानीय लोगों का भी हाथ रहा है। मगर यह लोग कभी नहीं पकड़े गए। जो पकड़ा गया वह अलगाववादी नेता या किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता व नेता ही मिला, लेकिन कभी भी इस बात को उजागर नहीं होने दिया जाता था।

आश्चर्य की बात यह है कि आतंकी घटनाक्रम को नेता अपने एक पैटर्न से समझाते आ रहे हैं कि आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर के युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं जिसको लेकर उनके दिल-दिमाग में कट्टरता आ जाती है और देश विरोधी गतिविधि के में शामिल हो जाते हैं और इसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ देते हैं। बात में काफी हद तक सच्चाई भी है लेकिन सवाल यह ही है कि आमजन जो जीवन में अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है उसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से मिलवाता कौन है या सबसे पहले माइंड कौन डायवर्ट करता है। इन सभी बातों के आधार पर तो यह तय हो जाता है कि देश की असली दुश्मन देश में ही हैं। हम हर छोटे से छोटे हमले पर भी पाकिस्तान पर बात टाल देते हैं। यह सत्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्रियां खोले बैठा है लेकिन हमें अपने देश में पल रहे पाकिस्तान परस्त लोगों व आतंकियों पर भी चर्चा करनी होगी। चर्चा हुई भी। पकड़े भी गए लेकिन पूर्ण रूप खत्म न होने पर जनता अभी भी परेशान है। हाल ही की स्थिति यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वापस घर आएंगे यह पता नहीं। चूंकि आतंकवादी किसी पर भी बिना वजह हमला कर रहे हैं। उद्देश्य स्पष्ट न होने की वजह से अभी तक तो यह माना जा रहा है कि दहशत फैलाने की वजह से यह सब हुआ। पड़ोसी देश से आतंकवाद पर कई बार चर्चा हुई लेकिन आजादी लेकर आज तक कोई हल नहीं निकला। हमें सबसे पहले उन लोगों पर एक्शन लेना होगा जो अपने ही देश में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह स्पष्ट है हर सरकार के कालखंड में वह खुलकर अंजाम देते आ रहे हैं। हर सरकार इसके इसके लिए चिंतित तो जरूर दिखती है लेकिन देश की जनता के मन में प्रश्न जरूर आता है कि बिना किसी की मिलीभगत से आतंकवाद कैसे संभव है। वैसे तो पूरे देश की जनता के लिए मुद्दा सुरक्षा का होता है लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए यह सर्वप्रथम रहता है। नई सरकार गठित होते ही जिस तरह आतंकवादियों हमले करते जा रहे हैं उससे वह क्या संदेश देना चाहते हैं यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत सभी दल के नेता परेशान हैं। कोई किसी की बुराई-भलाई नहीं कर रहा जिसे देखकर यह तो महसूस हो रहा है कि आतंकवाद को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए लेकिन जब से दोनों देश आजाद हुए हैं भारत सरकार ने इस मामले पर शुरुआत से चर्चा ही की है और हल आज तक नहीं निकला। कई बार सुना है कि पाकिस्तान को कड़े स्वर में समझा दिया गया है लेकिन उसका असर कभी नहीं दिखा। बहरहाल,नई सरकार बनते ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों ने वहां की जनता को दहला दिया है। हर रोज परिस्थितियां विषम होती जा रही हैं जिसको लेकर मौजूदा स्थिति में यह देश का बडा मुद्दा बन गया। अब आतंकवादी किसी विशेष को टारगेट न करके आमजन को निशाना बना कर एक अलग तरह की दहशत फैला रहे हैं।आतंकवादी अब जम्मू-कश्मीर की जनता के अलावा वहां के प्रवासियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसलिए अब आतंकवाद पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा।